(b) Yas, Sir.

(c) Consolidated sharges @ Rs. 40 per tcnne excluding loading charges have been fixed by the Cement Corporation of India (CCI.);

(d) Tenders were invited by the Cement Corporation of India through advertisement in the Press giving equal opportunity to all contractors including the local contractors.

(e) and (f) By tender as well as by negotiation with parties who submitted tenders.

Forest Based Industries in Gujarat

8080. SHRI R. P. GAEKWAD : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase forest-based industries during the remaining period of Sixth Plan and also during the Seventh Plan;

(b) if so, the number of such forest-based industries proposed to be set up in Gujarat State; and

(c) what would be their location and estimated cost and the expected time for produceion ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO) (a) to (c) Proposals for setting up forest based industries are considered on merits from time to time, having regard to adequate availability of raw materials on a sustained basis. No outlay has been provided in respect of forest based industries in the Annual Plan 1984-85 for Gujarat State, while the Seventh Plan has not yet been formulated.

महासागर विकास विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

8081. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महासागर विकास विभाग द्वारा देश के "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अलग भेजे गये मूल्यपत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से राज्यवार और वर्षवार हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गए मूल पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) महासागर विकास विभाग को उपरोक्त "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने मूलपत्र प्राप्त हुए; और

(घ) उनमें से अंग्रेजी और हिन्दी में लिखे गए मूलपत्रों की राज्यवार अलग-अलग संख्या कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) महासागर विकास विभाग के कोई सम्बद्ध 'अधीनस्थ कार्यालय' नहीं हैं ।

(ख) से (घ) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रालयों में श्रेणी-चार के कर्मचारियों को वर्दी, जूते कम्बल आदि की सप्लाई

8082. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह